साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 3-9 जून 2024 वर्ष-10, अंक-7

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

एमसपी पर गेहूं खरीद की सुस्त, सरकारी मंडियों का हाल बेहला

कैसे भरेगा देश का अन्न भंडार

मप्र में अब तक सिर्फ 48.20 लाख मीट्रिक टन हुई खरीद

गेहूं खरीदी में दूसरे राज्यों ने किया निराश, केंद्र को एमपी से उम्मीद

भोपाल। जागत गांव हमार

गेहूं की सरकारी खरीद अब सुस्त पड़ गई है। मंडियां सूनी पड़ने लगी हैं। अब इक्का-दुक्का किसान ही एमएसपी पर गेहूं बेचने आ रहे हैं। पिछले सात दिन के दौरान पूरे देश में सिर्फ 2,23,425.2 मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदा जा सका है। यानी पिछले एक सप्ताह के दौरान देश में रोजाना मुश्किल से 32 हजार टन गेहूं ही खरीदा गया।

30 जून को जब खरीद प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर बंद होगी तब तक मुश्किल से सरकार 270 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीद पाएगी। इसकी वजह यह है कि कई राज्यों में खरीद प्रक्रिया या तो खत्म हो गई है या खत्म होने वाली है। एफसीआई के अनुसार 30 मई सुबह तक सरकार सिर्फ 2,63,98,900 मीट्रिक टन गेहूं ही खरीद पाई है, जबकि 23 मई को खरीद 2,61,75,474.80 मीट्रिक टन थी। यानी पिछले एक सप्ताह में बहुत अधिक खरीद नहीं हुई है। जैसे-जैसे दिन बीत रहा है वैसे-वैसे मंडियों में एमएसपी पर बिकने के लिए गेहूं का आना कम हो रहा है। इस साल सरकार ने 372.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का टारगेट तय किया है। जिसे अचीव करने के लिए अभी 109 लाख टन गेहूं और खरीदना पड़ेगा।

कहां कब खत्म होगी खरीद

भारतीय खाद्य निगम के प्लान के अनुसार पंजाब में गेहूं की खरीद 31 मई को बंद हो गई है। 10 जून को हिमाचल प्रदेश, 15 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, जबकि 30 जून को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में खरीद खत्म हो जाएगी। हरियाणा में खरीद प्रक्रिया पहले ही बंद हो चुकी है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से ही कुछ उम्मीद बची है। बाकी सूबे तो इस मामले में पहले ही फिसड्डी साबित हो चुके हैं।

बोनस के बावजूद निराशा

मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों को 2275 रुपए की एमएसपी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है। इसके बावजूद दोनों सूबों ने अब तक अपना खरीद लक्ष्य पूरा नहीं किया है। दोनों राज्यों में गेहूं का प्रभावी सरकारी दाम 2400 रुपये प्रति क्विंटल है, इसके बावजूद किसान उपज बेचने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है, जबकि अब तक सिर्फ 48.20 लाख मीट्रिक टन की ही खरीद हुई है। इसी तरह राजस्थान में 20 लाख टन की बजाय सिर्फ 10.88 लाख टन की ही खरीद हो सकी है।

अब तक हुई खरीद

एफसीआई के अनुसार 30 मई सुबह तक सरकार लगभग 264 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीद पाई है। जिन 37,02,410 किसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनमें से अब तक सिर्फ 20,89,498 लाख किसानों ने ही सरकार को गेहूं बेचा। बाकी ने या तो उसे स्टोर कर लिया या फिर उसे व्यापारियों को ज्यादा दाम पर बेच दिया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक गेहूं बेचने वाले किसानों को अब तक 56,771.8 करोड़ रुपए एमएसपी के तौर पर भेजे जा चुके हैं।

चार लाख 21 हजार किसान होंगे डिफॉल्टर!

-सरकार ने कटौती के बाद भी आखिरी दिन तक लोन अकाउंट में जमा नहीं की रकम

-सहकारी बैंकों से खरीफ और रबी की फसल का 20 हजार करोड़ कर्ज दिया गया

-प्रदेश में इस साल 15 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था

इधर, मध्यप्रदेश में 4.21 लाख किसानों पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। वजह- उपार्जन केंद्र में गेहूं बेचने के बाद 2.25 लाख किसानों से लोन की रकम तो इनसे ले ली गई, लेकिन आखिरी तिथि होने के बावजूद यह रकम लोन अकाउंट में नहीं जुड़ी है। इसके अलावा 1.71 लाख किसानों को लेकर भी असमंजस है। सरकार ने लोन की राशि काटकर किसानों के लोन अकाउंट 1312 करोड़ रुपए की राशि ही डाली है। मप्र राज्य सहकारी बैंक के एमडी का कहना है कि रबी-खरीफ की फसलों का मिलाकर किसानों को जो कर्ज दिया है, उसमें से 50 प्रतिशत राशि मिल गई है। हालांकि, जमा रकम कितने किसानों की है, यह बताना मुश्किल है। बताया जाता है कि 1.94 लाख किसानों की ही राशि लोन अकाउंट में राशि जमा हुई।

तारीख पर दारोमदार

इस साल 15 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से सिर्फ 6.15 लाख ही गेहूं बेचने पहुंचे। इनमें से भी सिर्फ 1.94 लाख किसानों की राशि लोन खाते में जमा हुई है। बचे हुए 4.21 लाख की राशि जमा नहीं हुई या उसको लेकर असमंजस है। अब यदि यह तारीख नहीं बढ़ाई गई तो किसान डिफॉल्टर हो जाएंगे।

खाते में नहीं डली राशि

पिछले साल डिफॉल्टर किसानों की संख्या 12 लाख थी, जिसमें इस साल 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। अब यह 15 लाख हो गए हैं। वजह- गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसान से गेहूं तो खरीद लिया गया, उसमें से कर्ज की राशि काट ली, लेकिन समय सीमा में कर्ज खाते में नहीं डल पाई। राशि बैंक खातों में डालने में सात दिन का समय लग रहा है।

देरी पर होगी 14 फीसदी ब्याज से वसूली

कृषकों के लिए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तारीख 31 मई तय की थी। पहले यह 30 अप्रैल थी, जिसे खातों में राशि पहुंचने में हो रही देरी की वजह से बढ़ाया गया था। इसमें साफ कर दिया गया था कि तय समय सीमा में कर्ज जमा करने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज लगेगा। इससे एक दिन भी ज्यादा होने पर जब से कर्ज लिया है, तब से पूरे साल का 14 प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा। सहकारी बैंकों से फसल का 20 हजार करोड़ कर्ज दिया गया है।

पहले साल में ही 4.15 लाख पौधे लगाने की तैयारी

शरबती गेहूं के बाद अब बाजार में छाएगा सीहोर का अमरूद

सीहोर। जागत गांव हमार

सीहोर के शरबती गेहूं के बाद अब सीहोरी अमरूद भी देश भर के बाजार में धूम मचाएगा। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार सीहोर में प्रयोग कर रही है। गेहूं, सोयाबीन और चने के साथ जिले में 50 करोड़ रुपए की लागत से दो हजार एकड़ में अमरूद का बगीचा लगाने की कार्ययोजना बनाई गई है। अमरूद की खेती के लिए 200 पंचायत को 16 क्लस्टर में बांटकर किसानों का चयन किया जा रहा है। हर पंचायत से करीब 10 किसानों को क्लस्टर में लिया जाएगा। खास यह है कि सरकार न केवल किसानों को अमरूद की खेती के लिए एक एकड़ पर 1.80 लाख रुपए देगी, बल्कि फसल को बेचने के लिए मार्केटिंग भी करेगी।

फसल बेचने कंपनियों से अनुबंध- किसानों को उनकी फसलों का अच्छा भाव मिले, इसलिए फसल बेचने के लिए जिला प्रशासन कंपनियों से अनुबंध करेगा। पहले साल में 2000 एकड़ में 4.15 लाख अमरूद के पौधे लगाएगा। इसके लिए जिले से 1700 किसानों का हितग्राही के रूप में चयन किया जा रहा है।

नया करने का मिलेगा मौका

अभी एक साल में सिर्फ दो फसल गेहूं और चने की पैदावार होती है। जिले में क्लस्टर बनाकर अमरूद के बगीचे लगाने की कार्ययोजना पर काम चल रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। परंपरागत खेती से हटकर नया करने का मौका मिलेगा।

सरकार करेगी मार्केटिंग

बता दें कि इस प्रोजेक्ट में किसानों को फसल बेचने में खुद से मशक्कत नहीं करनी होगी, सरकार इन अमरूदों के लिए मार्केटिंग करेगी। इस प्रोजेक्ट में जिले की 200 पंचायतों में 16 क्लस्टर से किसान जुड़ रहे हैं।

- यहां 15 से 30 जुलाई तक बगीचा तैयार किया जाएगा। इसी दौरान पौधरोपण भी हो जाएगा। इससे पहले उद्यानिकी विभाग किसानों को इस खेती की ट्रेनिंग देगा। अच्छी किस्म के भी पौधे देगा।

आशीष तिवारी, सीईओ, जिला पंचायत, सीहोर

रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

आरबीआई ने कहा-देश में थम रहा मोटे अनाज का उत्पादन!

भोपाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। यह जानकारी मोटे अनाजों को लेकर है। आरबीआई ने कहा है कि भारत में मोटे अनाज का उत्पादन और रकबा दोनों ठहराव वाली स्थिति में हैं। यानी मिलेट का रकबा और उत्पादन दोनों स्थिर हो गया है, उसमें न तो वृद्धि है और न ही कोई गिरावट है। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। भारत, एशिया का 80 फीसद और पूरी दुनिया का 20 फीसद मोटा अनाज पैदा करता है। मोटे अनाजों के उत्पादन और रकबा में स्थिरता आने के पीछे कुछ खास वजह बताई गई है। इसमें सबसे खास है पतले अनाजों की खेती पर किसानों को दिया जाने वाला इनसेंटिव। इस इनसेंटिव को प्रोत्साहन राशि भी कह सकते हैं जो किसानों को अलग-अलग रूप में दी जाती है। इसी इनसेंटिव में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आता है। पतले अनाजों की खेती में एमएसपी का नियम है जिससे किसान इसकी अधिक से अधिक बुवाई करते हैं, जबकि मोटे अनाजों से बचते हैं। इसी तरह पतले अनाजों के लिए प्रोक्योमेंट स्कीम चलाई जाती है। सरकारी एजेंसियां अनाजों को खरीदती हैं और एक गारंटी कीमत देती हैं।

ट्रैक्टर से चलती कुट्टी मशीन, किसानों का काम हुआ आसान

पशुपालकों की अब चारा काटने में नहीं टूटेगी कमर

भोपाल। जागत गांव हमार

लगभग हर किसान पशुपालन जरूर करता है। लेकिन पशुओं के लिए चारा काटना सबसे कठिन काम होता है। अभी भी गावों में ज्यादातर किसानों के पास पुरानी तकनीक की कुट्टी मशीन ही होती है। इस मशीन को हाथ से ही चलाना होता है और चारे की कटाई में चलाने वाली की कमर टूट जाती है। इस मशीन को चैफ कटर मशीन भी कहते हैं। इस कुट्टी मशीन का क्या फायदा है और इसकी कीमत क्या है इस खबर में हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। ये एक ऐसी मशीन है जो ट्रैक्टर के पीछे आसानी लग जाती है और हर तरह का चारा बहुत तेजी से काट सकती है। चैफ कटर मशीन से चारा काटने के लिए आपको बस इसे ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट से जोड़ना है और फिर बेहद तेजी से ये मशीन चारा काटना शुरू कर देती है।

इतना ही नहीं, कई सारी चैफ कटर तो हाइब्रिड भी आती हैं। यानी कि ये मशीने ट्रैक्टर और इलैक्ट्रिक मोटर दोनों से चलती हैं। चैफ कटर मशीन एक बढ़िया चेचिस पर सेट रहती है, जिससे आप इसे ट्रैक्टर में पीछे लगाकर कहीं भी आराम से लेकर जा सकते हैं। इस मशीन में एक बड़े व्हील पर कई सारे हेवी ड्यूटी ब्लेड लगे होते हैं। इसका कोई खासा मेनटेनेंस भी नहीं होता है और ये कई घंटों तक लगातार काम कर सकती है। ये मशीन उन लोगों के लिए बेहद काम की है जो डेयरी का काम करते हैं और कुट्टी के लिए अलग से मजदूर लगाने पड़ते हैं।

ट्रैक्टर वाली कुट्टी मशीन के फीचर

ट्रैक्टर माउंटेड कुट्टी मशीन से हरा चारा और सूखा चारा दोनों काटे जा सकते हैं। इसमें 4 ब्लेड, 3 ब्लेड और 2 ब्लेड का ऑप्शन मिल जाता है। ब्लेड की संख्या को आप जरूरत के हिसाब से खुद से ही कम और ज्यादा कर सकते हैं। टैक्टर माउंटेड चैफ कटर मशीन में पीछे की ओर एक गियर भी होता है। इस गियर की मदद से आप चारे की मोटाई और बारीकी सेट कर सकते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे रिवर्स भी घुमा सकते हैं। इस गियर से मशीन की स्पीड भी एडजस्ट की जा सकती है। वहीं अगर इस मशीन का आप ऊंचा मॉडल खरीदते हैं तो इसमें पीछे एक कनवेयर बेल्ट भी मिलती है। इस कनवेयर बेल्ट की मदद से चारा अपने आप मशीन के अंदर चला जाता है और हाथ भी सुरक्षित रहते हैं। इस चैफ कटर मशीन में दो तरह कटा हुआ चारा निकालने के विकल्प मिलते हैं। मशीन का एक प्वाइंट खोलने पर कटा हुआ चारा सीधे जमीन पर गिरता है और दूसरा प्वाइंट चालू करने पर ये मशीन कटाई के बाद चारा सीधे ट्रॉली में भी गिरा सकती है। इससे आपकी मजदूरी भी बचती है।

चैफ कटर मशीन के फायदे

ट्रैक्टर से चलने वाली कुट्टी मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पशुपालकों और किसानों का श्रम और समय दोनों बच जाता है। इस मशीन में लगे गियर की मदद से चारे की मोटाई भी एडजस्ट की जा सकती है और साथ ही हर तरह का चारा काटा जा सकता है। चैफ कटर मशीन से कम समय में ज्यादा और अच्छी क्वलिटी का चारा काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस मशीन से आप छोटे चारे से लेकर गन्ना, मक्का और पराली तक आराम से काट सकते हैं। ट्रैक्टर वाली कुट्टी मशीन की क्षमता की बात करें तो एक घंटे में 4 से 7 क्विंटल चारा काट सकती है। ज्यादा एचपी वाली मशीनें तो 12 कुंतल प्रति घंटे की क्षमता से भी कटाई कर सकती हैं। चारा काटने की क्षमता इसकी स्पीड और चारे की मोटाई पर भी निर्भर करती है।

कीमत और सब्सिडी

ट्रैक्टर से चलने वाली कुट्टी मशीन की बाजार में कीमत 30 हजार से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन जो किसान या पशुपालक इसे खरीदना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से इसपर सब्सिडी भी मिल जाएगी। दरअसल, चारा काटने वाली मशीन पर सरकार पशुपालकों और किसानों को अच्छी-खासी सब्सिडी देती है। अलग-अलग चारा मशीनों पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। पॉवर से चलने वाली चारा मशीन पर 50 तक प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं हाथ वाली चारा मशीनों पर 70 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। कुट्टी मशीन पर सब्सिडी में छोटे, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

एरोपोनिक विधि से आलू की खेती

अब हवा में उगाएं आलू | घर की छत पर भी तकनीक आएगी काम

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत एक कृषि प्रधान देश है। 75 फीसदी से अधिक आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। पहले यहां के किसान हल-बैल से खेती करते थे, लेकिन अब समय के साथ-साथ खेती किसानी भी तकनीकी आधारित हो गई है, क्योंकि कृषि को उन्नत बनाने के लिए रोज नए-नए आविष्कार किए जा रहे हैं। इसके चलते भारतीय किसान अब तकनीक के मामले में अमेरिका और यूरोप को टक्कर देने लगे हैं। पहले जहां पूरे देश में आलू की खेती पारंपरिक विधि से की जाती थी, अब एरोपोनिक विधि से इसे हवा में ही उगाया जा रहा है। इससे किसानों की कमाई भी बढ़ गई है। एरोपोनिक फार्मिंग देश में बहुत ही तेजी से फैल रही है। इसमे पारंपरिक खेती के मुकाबले 10 गुना अधिक आलू की पैदावार होती है। यानी किसानों की कमाई भी 10 गुना अधिक होगी। खास बात यह है कि एरोपोनिक तकनीक की मदद से किसान अपने घर की छत पर भी आलू की खेती कर सकते हैं। ऐसे एरोपोनिक फार्मिंग विधि को हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ने तैयार किया है। इस तकनीक में नर्सरी में आलू के पौधों को तैयार किया जाता है। इसके बाद पौधों की रोपाई एक एरोपोनिक यूनिट में की जाती है।

एरोपोनिक फार्मिंग

एरोपोनिक तकनीक में आलू की लटकती हुई जड़ों के द्वारा उन्हें पोषण दिया जाता है। इस विधि से खेती करने के लिए किसान को मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में किसान घर की छत पर भी एरोपोनिक तकनीक से खेती कर सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि एरोपोनिक तकनीक से खेती करना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे किसान कम लागत और कम जगह में आलू की ज्यादा पैदावार मिल सकती है। ज्यादा पैदावार होने की स्थिति में किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा।

पूरे देश में किसान कर रहे खेती

एरोपोनिक फार्मिंग खेती करने का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है. इसके तहत खेती करने के लिए सबसे पहले आलू के उन्नत किस्म के पौधों की नर्सरी तैयारी की जाती है। इसके बाद नर्सरी में तैयार पौधों को गार्डनिंग यूनिट में पहुंचाया जाता है। इसके बाद पौधों की जड़ों को बावस्टीन में डुबो दिया जाता है। इससे फंगस का खतरा नहीं रहता है। फिर ऊंचा बेड बनाकर आलू के पौधों की रोपाई की जाती है। जब पौधे 10 से 15 दिन के हो जाते हैं तो एरोपोनिक यूनिट में पौधों की रोपाई करके कम समय में अधिक आलू का उत्पादन मिलता है। इस तकनीक की मदद से अब पूरे देश में किसान आलू उगा रहे हैं।

अगले साल के लिए तैयारियां अभी से शुरू

प्याज की सेल्फ लाइफ बढ़ाने स्टोरेज यूनिट बनाने की योजना

भोपाल। जागत गांव हमार

घरेलू आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 से प्याज निर्यात पर रोक लगा रखी थी, जिसे मई 2024 के पहले सप्ताह में खोल दिया गया है। इसके बावजूद मंडियों में प्याज की कीमत ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है। वहीं, प्रमुख राज्यों में खरीफ प्याज की बुवाई प्रभावित होने की आशंका के चलते उत्पादन पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी कम रहने का अनुमान है। ऐसे में अगले साल प्याज की किल्लत से बचने के लिए केंद्र प्याज स्टोरेज के लिए वातावरण अनुकूलित रेडिएशन प्रॉसेसिंग यूनिट स्थापित करने की तैयारियों में जुटा है। यूनिट के लिए चार बड़े शहरों को चिह्नित किया गया है, जहां सहकारी समितियां रेडिएशन प्रॉसेसिंग फैसेलिटी के लिए संभावना तलाश रही हैं। रेडिएशन प्रॉसेसिंग से प्याज की सेल्फ लाइफ लंबे समय के लिए बढ़ जाती है। देश की खाद्य सुरक्षा पक्का करने के उद्देश्य से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है और फिर खाद्यान्न को रेलवे रेक के माध्यम से भंडारण और वितरण के लिए पूरे देश में पहुंचाती है। स्टेशन पर रेल वैगन से खाद्यान्न को उतारकर ट्रक पर लोड किया जाता है और उसके बाद ट्रक के जरिए खाद्यान्न को गोदाम तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की उपलब्धता आसान रहने के चलते प्याज स्टोरेज के लिए भी रेडिएशन प्रॉसेसिंग यूनिट रेलवे स्टेशनों के पास स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों नेफेड और एनसीसीएफ को फेसेलिटी तलाशने के लिए निर्देशित किया गया है।

50 रेडिएशन यूनिट की पहचान कर रहीं समितियां

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव ने पिछले सप्ताह एक चर्चा के दौरान बताया था कि हम उपभोक्ता क्षेत्रों के आसपास 50 प्याज रेडिएशन केंद्रों की पहचान कर रहे हैं। अगर हम सफल रहे तो इस साल 1 लाख टन तक प्याज रेडिएशन प्रॉसेसिंग के जरिए स्टोरेज की जा सकेगी। सचिव ने कहा कि बफर स्टॉक के तुरंत ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नजदीक वातानुकूलित स्टोरेज फेसेलिटी रेडिएशन यूनिट लगाने की तैयारी चल रही है।

5 बड़े शहरों में लगेगी यूनिट

सहकारी समितियां नेफेड और एनसीसीएफ प्याज के 5 लाख टन बफर स्टॉक के लिए खरीद कर रहीं हैं। इन समितियों से सोनीपत, थाने, नासिक और मुंबई जैसे प्रमुख खपत केंद्रों के आसपास रेडिएशन प्रॉसेसिंग यूनिट ढूंढने और स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। पिछले साल महाराष्ट्र के निकट 1,200 टन के छोटी स्टोरेज कैपेसिटी पर रेडिएशन प्रॉसेसिंग की कोशिश की गई थी। इस बार बफर स्टॉक से अतिरिक्त 1 लाख टन प्याज रेडिएशन प्रॉसेसिंग के जरिए स्टोरेज करने की तैयारी है।

प्याज की बढ़ेगी सेल्फ लाइफ

केंद्र के अनुमान के मुताबिक प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कम पैदावार के कारण 2023-24 में कुल उत्पादन की तुलना में खरीफ सीजन 2024-25 में 16 प्रतिशत घटकर 250 लाख टन से अधिक उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादन में गिरावट की आशंकाओं के चलते केंद्र को प्याज के रेडिएशन प्रॉसेसिंग के जरिए स्टोरेज करने के लिए एक्शन लेने पर मजबूर किया है। रेडिएशन प्रॉसेसिंग के जरिए प्याज की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, प्याज का वजन, रंग और स्वाद लंबे समय बाद भी पहले जैसा ही बना रहता है।

गेहूं आयात करना बना चुनौती, एक अप्रैल 2024 को देश में गेहूं का स्टॉक 16 साल के निचले स्तर पर

ग्लोबली गेहूं उत्पादन का गणित भारत के लिए बड़ी चुनौती

गेहूं का गणित देश में गड़बड़ाया

भोपाल। जागत गांव हमार

गेहूं का गणित देश में गड़बड़ाया हुआ है। एक अप्रैल 2024 को देश में गेहूं का स्टॉक 16 साल के निचले स्तर पर था, जो बफर स्टॉक से थोड़ा सा अधिक था। इस बीच एमएसपी पर शुरू ही गई गेहूं की खरीद इस साल भी सुस्त दिखाई पड़ रही है। मसलन, लगातार तीसरी साल देश में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब, देश के खाली गेहूं भंडार के बीच गेहूं खरीद की सुस्त चाल डरा रही है। इससे उपजे हालात देश में गेहूं की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन हालातों में रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया गेहूं इंपोर्ट के लिए ड्यूटी खत्म करने की पैरवी करने लगा है। देश में गेहूं को लेकर उपजे हालातों के बीच अटकलों का बाजार गर्म है कि नई सरकार के गठन के बाद ड्यूटी फ्री गेहूं इंपोर्ट का रास्ता खुल सकता है। इस तरह की अटकलों से व्यापारी खुश हैं तो बेहतर दाम की चाह के लिए गेहूं स्टॉक कर रखने वाले किसानों के मन में कई सवाल है। आइए इसी कड़ी में गेहूं को लेकर दुनिया की सैर पर चलते हैं और समझते हैं कि दुनिया के किस देश में इस साल कितने गेहूं का उत्पादन हुआ है। क्योंकि दुनिया के देशों में उत्पादित गेहूं से ही भारत में गेहूं इंपोर्ट का गणित सुलझ सकता है। उम्मीद है कि इससे गेहूं इंपोर्ट के उलझे हुए गणित को सुलझाने में मदद मिलेगी।

गेहूं के ग्लोबल प्लेयर पर एक नजर

देश में गेहूं इंपोर्ट की गुत्थी को सुलझाने और किस देश में इस साल कितना गेहूं का उत्पादन से जुड़े सवाल के जवाब से पहले गेहूं के ग्लोबर प्लेयर पर एक नजर डालते हैं। साल 2023 के उत्पादन आंकड़ों के हिसाब से गेहूं के ग्लोबर प्लेयर की रैंकिंग को समझें तो 136 मिलियन मीट्रिक टन के साथ चीन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक रहा, इसके बाद 133 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ यूरोपियन यूनियन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक रहे। इसके बाद भारत का नाम हैं, जो 110 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ ग्लोबली गेहूं तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चौथे नंबर पर 91 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ रूस, 49 मिलियन मीट्रिक टन के साथ अमेरिका, 33 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कनाड़ा, 28 मिलियन मीट्रिक टन के साथ पाकिस्तान, 25 मिलियन मीट्रिक टन ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में शामिल है। इसके बाद यूक्रेन शामिल है।

रूस-यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में कम उत्पादन

यूएसडीए ने जहां इस साल ग्लोबली गेहूं उत्पादन में 10 एमएमटी बढ़ोतरी का अनुमान जारी किया है, लेकिन रूस-यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में गेहूं उत्पादन में कमी का अनुमान जारी किया है। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल यूरोपियन यूनियन में गेहूं उत्पादन 2.2 एमएमटी कम होने के साथ 132 एमएमटी रह सकता है। इसी तरह रूस में 3.5 एमएमटी गिरावट के साथ 88 एमएमटी गेहूं पैदावार का अनुमान यूएसडी ने जारी किया है। वहीं यूक्रेन में इस साल 21 एमएमटी गेहूं उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 2 एमएमटी कम होगा।

दुनिया में गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड अनुमान

भारत में गेहूं का गणित उलझा हुआ है। बेशक देश में इस बार रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान है, लेकिन गेहूं का मौजूदा बाजार भाव, गेहूं का कम सरकारी भंडार, गेहूं की सरकारी खरीद की सुस्त चाल ही गेहूं इंपोर्ट की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन गेहूं इंपोर्ट की संभावनाओं से पहले दुनिया में इस साल गेहूं के उत्पादन को समझना भी जरूरी है। संयुक्त राज्य कृषि विभाग यानी इस बार ग्लोबली गेहूं का उत्पादन 798 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 10 एमएमटी अधिक है, जिसमें भारत का गेहूं उत्पादन पिछले साल की तुलना में 314 एमएमटी अधिक होने के साथ 114 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान जारी किया गया है। यूएसडीए के मुताबिक चीन में गेहूं उत्पादन इस साल 140 एमएमटी होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 3.4 एमएमटी अधिक है। इसी तरह अमेरिका में 1.2 एमएमटी बढ़ोतरी के साथ गेहूं उत्पादन 50 एमएमटी होने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में इस साल गेहूं उत्पादन पिछले साल की तुलना में क्रमशः 3 और 2 एमएमटी अधिक हो सकता है।

ग्लोबल गेहूं उत्पादन और इंपोर्ट

भारत में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है, लेकिन इन सबके बीच देश में गेहूं इंपोर्ट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अगर ये मान भी लिया जाए कि नई सरकार गेहूं इंपोर्ट की राह आसान करने के लिए 44 फीसदी ड्यूटी हटाएगी, लेकिन इसके बाद भी जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबली गेहूं उत्पादन का गणित भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इस साल रूस-यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में गेहूं का उत्पादन कम है। तो वहीं दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। वहीं युद्ध की जियो पॉलिटिक्स में दुनिया के देश गुों में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक रूस और यूक्रेन में गेहूं की पैदावार खपत से अधिक होती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन और रूस की राहें अलग-अलग हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूक्रेन पर ही यूरोपियन यूनियन को गेहूं इंपोर्ट की जिम्मेदारी दिखाई पड़ती है। वहीं पिछले साल 10000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं इंपोर्ट करने वाले चीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की जैसे देशों की मांग पूरी करने की जिम्मेदारी भी ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, कनाड़ा जैसे देशों पर है। इन हालातों में भारत किस देश और किस दाम पर गेहूं इंपोर्ट करेगा, ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ता है। हालांकि रूस से गेहूं इंपोर्ट की संभावना भारत के लिए है, लेकिन कम उत्पादन में रूस भारत को किस दाम में गेहूं इंपोर्ट करेगा, ये देखने लायक होगा।

-किसान जानें विधि, करें पहचान और बचाव

सोयाबीन के लिए खतरनाक पीला मोजैक रोग

भोपाल। जागत गांव हमार

खरीफ सोयाबीन की बुवाई का सीजन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में किसान इस बार बंपर रकबे में बुवाई कर रहे हैं। किसानों की उम्मीद है कि इस बार सोयाबीन का बंपर उत्पादन होगा। लेकिन उन्हें इसकी फसल में लगने वाले सोयाबीन मोजेक वायरस जनित रोग को लेकर भी चिंता है। क्योंकि इस रोग के लगने के बाद फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। साथ ही उत्पादन में भी गिरावट आती है। इससे किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। सोयाबीन मोजेक वायरस जनित रोग है, जो पॉटीवायरस के कारण होता है। फसल में यह रोग सफेद मक्खी की चपेट में आने से लगता है। पहले सोयाबीन की पत्तियों पर सफेद मक्खियां बैठती हैं। इससे पौधे संक्रमित हो जाते हैं। फिर एक पौधे से दूसरे पौधे तक संक्रमण धीरे-धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। हालांकि, लगातार वर्षा होने पर इस रोग के संक्रमण का असर फसलों पर नहीं होता है। लेकिन बारिश तीन से चार दिन के अंतराल पर होती है, तो संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका बढ़ जाती है।

उपज हो सकती है प्रभावित- खास बात यह है कि मोजेक वायरस जनित रोग सोयाबीन के साथ-साथ दलहनी फसलों को भी प्रभावित करता है। कहा जाता है कि यदि समय रहते रोग पर काबू नहीं पाया गया, तो 50 से 90 प्रतिशत तक सोयाबीन की उपज प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसानों को इस रोग को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे में किसानों को इस रोग की पहचान होनी चाहिए। वे नीचे बताए गए तरीकों से मोजेक वायरस जनित रोग की पहचान कर सकते हैं।

कैसे करें रोग की पहचान

पीला मोजेक रोग लगने पर फसल की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। साथ ही इसके प्रभाव से पत्तियां खुरदुरी हो जाती हैं और उन पर सलवटें पड़ने लगती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीला मोजेक रोग के चलते संक्रमित पौधे नरम पड़कर सिकुड़ने लगते हैं। इस दौरान फसल की पत्तियां गहरा हरा रंग ले लेती हैं और पत्तियों पर भूरे और सलेटी रंग के धब्बे भी पड़ने लगते हैं। फिर फसल में अचानक सफेद मक्खी पनपने लगती है और इससे फलसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए ये लक्षण दिखाई पड़ते ही उपचार शुरू कर देना चाहिए।

इस तरह करें बचाव

पीला मोजेक रोग से फसल को बचाने के लिए खेत में जगह-जगह पर पीला चिपचिपा ट्रैप लगाएं। इससे रोग नहीं फैलता है। साथ ही इन रोगों को फैलाने वाले वाहक सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए मिश्रित कीटनाशक थायोमिथोक्सम+ लैम्ब्डा सायहेलोथ्रिन (125 मिली/हे) या बीटासायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड (350 मिली/हे) का छिड़काव करें। इसके अलाावा पीले मोजेक रोग से फसलों को बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक के घोल में बीज को डुबोने के बाद रोपना चाहिए। इससे फसल में रोग नहीं लगता है और उत्पादन भी अच्छा होता है।

सड़क पर उतरे 400 किसान, हाईवे किया जाम

प्रदेश के खरगोन में फसलों पर गहराया बिजली संकट!

खरगोन। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के खरगोन में उस समय यात्रियों को परेशान होना पड़ा, जब चिलचिलाती धूप में 400 किसान सड़कों पर उतर आए। बिजली नहीं मिलने और खेतों में फसलें नष्ट होते देख गुस्साए किसानों ने बड़वाह-धामनोद राज्य मार्ग पर धरना दिया। इस दौरान करीब 4 घंटे सड़क जाम रही। दो किलोमीटर तक यात्री जाम में फंसे रहे। दरअसल, मामला ग्राम छोटी खरगोन का है, जहां 5 दिनों से लाइट नहीं है। खरीफ की फसलें किसानों ने खेतों में लगाई हैं, लेकिन बिजली नहीं होने से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा खेतों में फसलें खराब होने लगी हैं। किसानों की मांग है कि तुरंत बिजली सप्लाई चालू करके अगले तीन दिनों तक 14 से 18 घंटे दी जाए, ताकि नष्ट होती फसलों को बचा सकें।

5 दिन से बंद खेतों की लाइट

धरने पर बैठे किसान संतोष पाटीदार ने बताया कि गांव में करीब 400 किसान हैं, जिन्होंने कपास, मिर्च, करेला, भुट्टे जैसे अन्य अनाज और सब्जी की फसलें लगाई हैं। पानी नहीं मिलने से फसलें खराब हो रही हैं। 5 दिनों से खेतों की लाइट बंद है। एमपीईबी के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूछने पर छोटे अधिकारी/कर्मचारी कहते है फॉल्ट ढूंढ रहे हैं।

50 साल में पहली बार ऐसी स्थिति

वहीं, किसान नरेंद्र सिर्वी ने बताया कि फसलों की स्थिति बहुत गंभीर है। बिजली विभाग का कोई अफसर ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों की फसलें अंकुरित होकर तैयार हो गई हैं। पानी नहीं मिला तो फसलें खराब हो जाएंगी। उन्होंने कहां कि गांव में 50 वर्षों का रिकॉर्ड है, कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, इतने दिनों तक कभी लाइट बंद नहीं हुई। पास के गांवों में लाइट चालू है, लेकिन इस गांव में अभी तक नहीं दी है।

भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में एक चौथाई योगदान

हर साल 1 जून को 'विश्व दुग्ध दिवस' मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2001 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की थी। 'विश्व दुग्ध दिवस' मौके पर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मीनेश शाह ने वैश्विक पोषण और खाद्य सुरक्षा में दूध की मौलिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। डेयरी फार्मिंग के महत्व और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर जोर देते हुए, उन्होंने बताया है कि एनडीडीबी और भारत सरकार डेयरी क्षेत्र में लचीलापन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कैसे प्रतिबद्ध हैं।

बढ़ती जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं और उपभोग पैटर्न सदी के मध्य तक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के लिए प्रेरक शक्तियां हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जनसंख्या 2020 में 1.38 बिलियन से बढ़कर 2030 तक लगभग 1.5 बिलियन हो जाएगी। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से भूख और कुपोषण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए प्रति व्यक्ति भोजन का सेवन बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है।

उन्होंने आगे कहा, जैसा कि हमने देखा है कि कृषि और डेयरी जैसे संबद्ध क्षेत्र, आजीविका, खाद्य और पोषण सुरक्षा और हमारे देश के सामाजिक-आथिज़्क विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये क्षेत्र आने वाले दशक में लाभकारी रोजगार अवसरों के साथ एक स्थायी तरीके से समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वही, वर्तमान में दूध सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो 80 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे रोजगार देती है।

डेयरी उद्योग रोजगार और आय-सृजन का है अच्छा रास्ता: शाह ने आगे बताया कि भारत में दूध उत्पादन 2014-15 से 2023 तक लगभग 6प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है, जबकि वैश्विक वृद्धि दर लगभग 2त्न है। अधिकांश दूध का उत्पादन उन पशुओं से होता है जिन्हें छोटे और सीमांत तथा भूमिहीन किसान पालते हैं जिनके झुंड में केवल 2-3 पशु होते हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान देने के अलावा, डेयरी उद्योग रोजगार और विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के सीमांत किसान और महिला किसानों के लिए आजीविका को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इसके बाद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में दूध उत्पादों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। यह क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास को गति देने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा, यह विशेष रूप से महत्वपूणज़् हो रहा है, जब सकल मूल्य-वर्धित में फसलों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है, जबकि पशुधन की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। दूध उत्पादन में इस बेहतर वृद्धि के परिणामस्वरूप, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर लगभग 460 ग्राम प्रतिदिन हो गई है, जो अनुशंसित आहार भत्ते से भी अधिक है। इसलिए, डेयरी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में पोषण प्रदान करने में भी मदद करता है, क्योंकि कुल उत्पादित दूध का लगभग 40 प्रतिशत दूध उत्पादक परिवारों द्वारा खपत किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डेयरी ज्यादातर फसल उत्पादन प्रणाली से जुड़ी हुई है और इन दोनों के बीच की पूरकता इसे दुनिया की सबसे टिकाऊ प्रणालियों में से एक बनाती है, साथ ही यह गरीबों और महिलाओं के लिए भी लाभकारी है। यह अक्सर सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कठिन समय में बीमा के रूप में काम आता है। डेयरी क्षेत्र सुरक्षा में समानता लाने में मदद करता है क्योंकि पशुधन परिसंपत्तियों का वितरण कृषि भूमि की तुलना में कहीं अधिक न्यायसंगत है। इसके अलावा, उन्होंने बताया, कुल किसानों में से लगभग 85प्रतिशत छोटे और सीमांत हैं और सामूहिक रूप से वे लगभग 47त्न कृषि भूमि के मालिक हैं जिसके पास करीब 75प्रतिशत दुधारू पशु हैं। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में निवेश किया गया 1 रुपया भी ग्रामीण क्षेत्र की बहुआयामी चुनौतियों जैसे बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बहुत अधिक रिटर्न देता है। महिलाएं हमेशा से ही डेयरी गतिविधियों में सबसे आगे रही हैं। यह उन्हें लाभदायक रोजगार प्रदान करता है क्योंकि वे चारा और दूध निकालने जैसी प्रमुख पशुपालन गतिविधियां करती हैं।

भारत का कृषि ऋण वितरण वित्त वषज़् 2023-24 में बढ़ा, लक्ष्य से 24 प्रतिशत अधिक 25 लाख करोड़ पर पहुंचा: भारत का कृषि ऋण वितरण वित्त वषज़् 2023-24 में लक्ष्य से 24 प्रतिशत अधिक रहा है। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में कुल कृषि ऋण बढ़कर 24.84 लाख करोड़ रुपये हो गया।

डेयरी सहकारी समितियों से जुड़ी किसान महिलाएं: मीनेश शाह ने कहा कि वर्तमान में डेयरी सहकारी समितियों से जुड़ी लगभग 2 करोड़ किसान महिलाएं हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा डेयरी का काम सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। डेयरी के साथ-साथ इससे जुड़ी मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भूमि या सिंचाई जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता न होने के कारण यह क्षेत्र ग्रामीण समृद्धि के लिए एक प्रभावी माध्यम बन गया है। आज, लगभग 8 करोड़ किसान परिवार दूध उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए हैं। भारत वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा उत्पादित कर रहा है और हम पिछले कई वर्षों से इस वृद्धि को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, डेयरी को नीति आयोग द्वारा उन क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूध के अलावा, एनडीडीबी किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद मूल्य श्रृंखला और बायोगैस पहल के माध्यम से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहा है। यह जीवाश्म ईंधन के उपयोग से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में भी मदद करता है और रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देता है। यह अंततः कृषि भूमि की उर्वरता और स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। अंत में उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के जीवन को बदलने की अपार संभावनाएं हैं। एनडीडीबी और भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।

पशुओं से इंसानों में क्षय रोग (टीबी): कारण एवं बचाव

» डॉ. राकेश कुमार बरहैया
» डा. मनीष जाटव
» डॉ. रुपेश वर्मा
» डॉ. अनिल सिंधे
» डॉ. हरी आर

सहायक प्राध्यापक, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर

क्षय रोग इंसानो, जानवरो एवं पक्षियों को होने वाला एक बहुत ही खतरनाक रोग है। यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है, जोकि प्रमुख रूप से तीन प्रकार के होते है। 1.माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस (इंसानो में क्षय रोग करने वाले) 2. माइकोबैक्टेरियम बोविस (जानवरो में क्षय रोग करने वाले) 3. माइकोबैक्टेरियम एवियम (पक्षियों में क्षय रोग करने वाले)। क्षय रोग (टी. बी.) एक जूनोटिक रोग है, जो जानवरों से इंसानो में या इंसानो से जानवरों में फैलती है, और यही इसे एक भयंकर रोग बनाता है ।

जानवरों में क्षय रोग के लक्षण: यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है, और प्रारम्भिक अवस्था में रोगी पशु में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। जब यह जीवाणु फेफणों (लंग्स) तक पहुँच जाता है तब रोगी को रुक रुक कर बुखार (ज्वर) आने लगता है। रोगी पशु को सुखी खांसी आती है और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जब यह रोग आंतो तक पहुँच जाता है तब उसको दस्त लग जाते है। क्षय रोग जीवाणु रोगी पशु के दूध के माध्यम से बाहर निकलते हैं। दूध पतला होकर अंत में पनीला हो जाता है। पशुओं में इस रोग की अवधि कुछ महीनो से लेकर वर्षों तक हो सकती है। क्षय रोग के जीवाणु रोगी पशु के लार (खंखार), मल, मूत्र व दूध द्वारा बाहर निकलते है। क्षय रोग से ग्रसित पशु के मांस में भी इस रोग के जीवाणु मौजूद होते है। गाय, भैंसो के अलावा क्षय अन्य पशुओ जैसे की भेड़, बकरी ,सूअर व् ऊंट आदि को भी हो सकता है और ये सभी पशु इंसानो में रोग फैला सकते हैं।

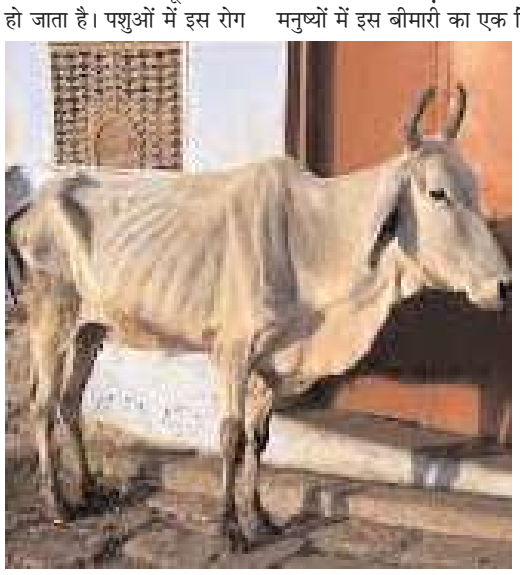

इंसानो में क्षय रोग के लक्षण: क्षय रोग के मुख्य लक्षण फेफड़ों के प्रभावित होने के कारण होते है, जैसे की रोगी को बुखार आना, धीरे-धीरे कमजोर होना, खांसी आना, भूख न लगना, वजन घटना व थूक के साथ खून आना। यह लक्षण मुख्यतः मनुष्यो द्वारा मनुष्यो में फैली हुई क्षय रोग की अवस्था में होते है, लेकिन जब क्षय रोग के जीवाणु पशुओ से मनुष्यो में जाते है तो मुख्यतः मनुष्यों की अंतड़ियो, चमड़ी , ग्रंथियों , गुदेज़् व् प्रजनन अंगो को प्रभावित करते है परन्तु ऐसे जीवाणु मनुष्यों के फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

पशुओं से मनुष्यो में क्षय रोग (टी. बी.) फैलने के कारण

1. रोगी पशु का कच्चा दूध व ऐसे दूध से बने पदार्थों के सेवन से।

2. रोगी पशु के थानों से सीधे ही मुंह में दूध लेकर पीना, जो कि गावों में देखा जाता है।

3. रोगी पशु का कच्चा या अधपका मांस खाने से भी यह रोग हो जाता है।

4. रोगी पशु के संपकज़् में रहना जैसे - हवाबंद, नमी वाले व तंग स्थानों में साथ-साथ रहना।

रोग से बचाव एवं रोकथाम: क्षय रोग ग्रस्त पशु, मनुष्यों में इस बीमारी का एक ींत हो सकते हैं। अतः पशुओं में इस रोग की रोकथाम आवयश्क है। पशुओं में इस रोग की रोकथाम इन तरीकों से किया जा सकता है।

1. पशुओं को खरदीने से पहले या जब कभी भी इस बीमारी के होने का संदेह हो तो पशुओं का टुबरकुलीन टेस्ट करवाना चाहिए और जो पशु रोगी पाए जाये तो उन सभी को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए।

2. पशुओं के बांधने का स्थान साफसुथरा, खुला तथा हवादार होना चाहिए।

3. पशुओं को साफ पानी व अच्छी खुराक देना चाहिए।

4. जिस स्थान या पशु बाड़े में क्षय रोग (टी. बी.) ग्रस्त पशु रहा हो, वहा से अन्य पशु को हटा लेना चाहिए। रोगी पशु के गोबर, पेशाब, िव व चारे आदि को जला या गड्ढे में दबा देना चाहिए पशुघर यदि पक्का हो तो उसे जीवाणु नाशक दवाई से अच्छे से धो लेना चाहिए। इंसानो में इस रोग के बचाव के लिए बी.सी.जी. का टीका छोटी आयु में लगाया जाता है। क्षय रोग (टी. बी.) से ग्रसित व्यक्ति का तुरंत चिकत्सीय सुविधा का उपयोग कर इलाज करवाना चाहिए।

ऊंटनी का दूध गुणों का भंडार, कैंसर सहित कई रोगों से करता है बचाव

गाय, भैंस और बकरी के दूध के बारे में तो अक्सर बात होती ही है, लेकिन ऊंटनी के दूध के बारे में कम लोग जानते हैं। आधुनिक विज्ञान की मदद से किसान दूध के लिए गाय के बदले ऊंट पाल सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों सोनिया सांगवान और रमन सेठ के अनुसार औसतन एक ऊंटनी एक दिन में 2 से 3 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। अच्छी देखभाल की जाए तो यह 4 से 5 लीटर तक उत्पादन कर सकती है। मानव और पशु अध्ययनों में पाया गया कि ऊंटनी का दूध मधुमेह, कैंसर, विभिन्न प्रकार के संक्रमण, भारी धातु विषाक्तता, कोलाइटिस और शराब से प्रेरित विषाक्तता से निपटने और लीवर के लिए फायदेमंद होता है।

ऊंटनी के दूध में अधिक चिपचिपाहट होती है। इसमें उच्च विटामिन 'सी' और वसा की मात्रा (2.9 से 5.5 प्रतिशत) होती है। घुमंतू लोगों द्वारा ऊंटनी के दूध का उपयोग सदियों से औषधीय रूप में किया जाता रहा है। यह दूध मानव शिशुओं के लिए मां के दूध के सबसे बेहतर विकल्पों में से एक। ऊंटनी का दूध सामान्य गाय के दूध की तुलना में स्वाद में थोड़ा नमकीन होता है। वैज्ञानिकों ने इसके कई फायदे बताए हैं।

लीवर को ठीक रखने में मददगार: वैज्ञानिको के अनुसार इसके दूध का उपयोग लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है। लीवर कुछ खास एंजाइम को रक्त में डालता है। वायरस अटैक की वजह से लीवर डैमेज की स्थिति बनती है, तो इन एंजाइम का स्तर बढ़ जाता है। हैपिटाइटिस-सी के मरीजों में इसका दूध लीवर एंजाइम के बढ़े हुए स्तर को कम करने में मदद करता है, यह लीवर के स्वास्थ्य की दृष्टि से एक सकारात्मक संकेत है।

वहीं, दूसरी ओर ऊंटनी का दूध बढ़े हुए ग्लोब्यूलिन (रक्त में मौजूद एक प्रकार के प्रोटीन) के स्तर को कम कर सकता है। लीवर के रोग के दौरान कम होने वाले टोटल प्रोटीन, प्लेटलेट्स (एक प्रकार के रक्त सेल्स और एल्ब्यूमिन), लीवर द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन के स्तर को बढ़ाने में भी यह मदद करता है।

इसके दूध में एंटी-डायरियल गुण होते हैं। बच्चों में रोटावायरस से दूषित खाना खाने के कारण दस्त लगने की स्थिति में इसका दूध लाभदायक हो सकता है। इसका दूध एंटी-रोटावायरस एंटीबॉडी से भरपूर होता है।

खाद्य एलर्जी से बचाव: इसके दूध में रोग से लड़ने वाले इम्युनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। इन इम्युनोग्लोबुलिन की एलर्जी के लक्षणों को कम करने में महत्वपूणज़् भूमिका मानी जाती है। ऐसा दावा किया जाता है कि इसके दूध का सेवन कैंसर से बचाव कर सकता है। दरअसल इसके दूध का उपयोग ऑटोफैगी को बढ़ावा देकर आंत और स्तन कैंसर कोशिकाओं पर एंटीप्रोलिफेरेटिव प्रभाव (बढ़ती कोशिकाओं को रोकने का प्रभाव) डालता है। ऑटोफैगी सेल्स से जुड़ी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कोशिकाएं स्वयं से अनावश्यक घटकों को हटाने का काम करती हैं।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार: ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर को हृदय रोग के लिए एक बड़ा जोखिम कारक माना जाता है। खमीरयुक्त इसके दूध का उपयोग हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक प्रभाव पैदा करता है। इसके दूध के बायोएक्टिव व पेप्टाइड्स और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच प्रतिक्रिया होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ऊंटनी के दूध में ओरोटिक एसिड (न्यूक्लिक एसिड के चयापचय में एक मध्यवर्ती के रूप में काम करता है) होता है, जिसे चूहों और मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

अभी तक बीटी कपास के लिए गुजरात और आंध्र प्रदेश पर थी निर्भरता

» धार जिले के 80 से अधिक किसानों से कंपनी करेगी अनुबंध

» कृषि विभाग के माध्यम से किसानों और कंपनी के मध्य होगा अनुबंध

प्रदेश में पहली बार बीटी कपास बीज का उत्पादक बनेगा किसान

धार। जागत गांव हमार

भीषण गर्मी में बीटी काटन (कपास) बीज के लिए मालवा-निमाड़ अंचल के किसानों ने कतार में लगाकर अपना पसीना बहाया था। ऐसे हालात आने वाले समय में निर्मित नहीं हों, इसके लिए धार, बड़वानी और खरगोन जैसे कपास उत्पादक जिलों में किसानों को पहली बार बीटी काटन के बीज का उत्पादक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी और किसानों के बीच अनुबंध होगा। शुरुआत में करीब 50 हेक्टेयर में बीज का प्रोडक्शन लेने की योजना है। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसानों को बीज के लिए कृषि विभाग लाभ के साथ आत्मनिर्भर बनाने की पहल कर रहा है। जल्द ही कंपनी व किसानों के मध्य अनुबंध हो जाएगा। इसके नतीजे वर्ष 2025 में देखने को मिलेंगे। कपास के बीटी बीज केवल गुजरात, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में किसान व कंपनी मिलकर तैयार करते हैं। किसानों को ऊंचे दाम पर हर साल कंपनी से बीज खरीदना होते हैं। मध्य प्रदेश के धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर सहित अन्य जिलों में करीब 15 लाख पैकेट बीज का मार्केट है। एक पैकेट का जन 475 ग्राम होता है। बड़ा बाजार होने के बाद भी मप्र बीज उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। बीज के लिए गुजरात पर निर्भरता है। धार, खरगोन व बड़वानी के किसानों तथा निजी कंपनी के बीच बीटी काटन बीज के प्रोडक्शन के लिए अनुबंध होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसके लिए खुद टीम के माध्यम से किसान के खेतों में बोवनी करवाएंगी। बीटी कपास आनुवंशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी कपास किस्म है, जो वालवर्म कीट का सामना करता है। धार जिले में 80 से अधिक किसानों से कंपनी अनुबंध करेगी। इन किसानों के खेत पर कंपनी के निदेर्शानुसार पूरी प्रक्रिया होगी। समय-समय पर बीज हाईब्रिड करने व कीटनाशक देने की प्रक्रिया होगी।

किसानों के लाभ का गणित

धार जिले में नुजीविडू सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अनुबंध होगा। मोटे अनुमान के तहत एक पौधे में 50 कपास फूल के हिसाब से प्रति एकड़ छह से सात क्विंटल की उपज प्राप्त होती है। इसमें 65 प्रतिश यानी लगभग 3.90 क्विंटल रेशे वाले बीज प्राप्त होते हैं। ये कंपनी द्वारा अनुबंध के आधार पर नौ प्रतिशत कटौती कर रेशे लगभग 3.4 क्विंटल बीज 500 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद लेगी। इसके बाद जिनिंग प्लांट बडोली, गुजरात में भेजा जाएगा। शेष बचे 35 प्रतिश कपास के रेशों को बाजार की दर से खरीदी जाएगा। इस प्रकार कपास बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए एक एकड़ में लगभग 75000 रुपए की लागत आएगी। उसे पर किसान को शुद्ध आय एक लाख 15 हजार होगी, जबकि साधारण रूप में कपास की खेती करने वालों को लागत निकालना भी मुश्किल होता है। कंपनी की बाय बैक यानी खरीदने की गारंटी रहती है। इससे किसान को नुकसान नहीं होता है। कंपनी अपने माध्यम से पैसा खर्च करती है। इससे किसानों को आर्थिक बोझ भी कम आएगा। बीज उत्पादक अगले सत्र के लिए बीज के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। स्थानीय प्रोडक्शन होने से प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। परिवहन व अन्य खर्च कम होने से कंपनी स्थानीय बाजार में इसे कम दाम में बेचती है। ऐसा गुजरात में होता भी है।

क्या है बीटी काटन

बीटी कपास आनुवांशकीय परिवर्तित फसल है। इसमें बेसिलस थ्यूरेनजिनेसिस बैक्टीरिया के एक या दो जीन फसल के बीज में आनुवांशकीय अभियांत्रिकीय तकनीक से डाल दिए जाते हैं। इससे पौधे के अंदर क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। इससे विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है, जो कीटों को नष्ट कर देता है।

किसानों को बीटी काटन के बीज के उत्पादन कार्यक्रम के लिए कृषि विभाग ने पहल की है। धार जिले में 80 किसानों व कंपनी के बीच अनुबंध होगा। कंपनी की निगरानी में बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका लाभ किसानों को होगा।

जीएस मोहनिया, उप संचालक, कृषि विभाग, धार

लहसुन एक मसाला है, लेकिन इसे सब्जी की तरह स्टोर करके नहीं रखा जा सकता

मांग बढ़ने से शाजापुर में 16 हजार रुपए प्रति क्विंटल लहसुन

शाजापुर। जागत गांव हमार

गर्मी के मौसम में अब लहसुन के दाम भी 15 हजार रुपए प्रति क्विंटल को पार कर गए हैं, वहीं प्याज के भाव भी 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर चल रहे हैं। कृषि उपज मंडी शाजापुर में बीते एक महीने में लहसुन के दाम में दो से तीन हजार प्रति क्विंटल बढ़ोतरी देखने को मिली। दो दिन पूर्व 726 क्विंटल लहसुन की आवक रही और भाव न्यूनतम 2000 और अधिकतम 15 हजार 500 तक रहे। दरअसल, लहसुन के दाम बढ़ने के पीछे जो मुख्य वजह किसान बता रहे हैं वह है लहसुन की फसल का खराब होना और उपज का कम होना है। वहीं किसानों व व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में लहसुन के दाम में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी।

किसानों का कहना है कि लहसुन की एक खासियत है कि यह मसाला तो है, लेकिन सब्जी की तरह है, इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। कुछ दिन में यह खराब हो जाता है। इसका स्टाक तभी किया जा सकता है, जब डिहाइड्रेशन करके लहसुन से पानी को सोख लिया जाए। ऐसा काफी कम जगह पर किया जा रहा है। लहसुन की डिमांड साल भर रहती है, लेकिन इसके मंडी में आने का समय सात से आठ महीने होता है। वर्तमान में डिमांड बनी हुई है, सप्लाई के मुताबिक मांग ज्यादा है। इसके अलावा हर महीने इसकी जरुरत रहती है, डिमांड और सप्लाई के चलते दाम अच्छे बने हुए हैं। इस बार लहसुन का उत्पादन कम हुआ है, जिसके चलते मांग पूरे साल बनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

चार लाख के खर्चे में 15 लाख का उत्पादन

जिले के बोलाई निवासी ब्रजेश वर्मा ने 10 बीघा क्षेत्र में लहसुन की फसल का उत्पादन किया था, उनके करीब नौ क्विंटल प्रति बीघा से ज्यादा का लहसुन उत्पादित हुआ है। वह मंडी में एक बार आकर अपना माल बेच चुके हैं, अभी लहसुन का स्टाक भी किया है। मंडी में लहसुन का 15 हजार प्रति क्विंटल के भाव में राशि उन्हें मिली है। उनका कुल उत्पादन करीब 100 क्विंटल के आसपास है। करीब 15 लाख रुपए की फसल उन्होंने उगाई है, खर्चा चार लाख के आसपास हुआ है।

रतलाम में लहसुन की आवक 13 हजार कट्टा पार

पांच माह पहले 35 हजार क्विंटल तक बिक चुके लहसुन के दाम इन दिनों गिरकर 20 हजार के आसपास पहुंच गए हैं। रतलाम में आवक बढ़ने के बाद भी पिछले एक सप्ताह से दामों में बहुत ज्यादा-चढ़ाव नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद आवक बढ़ने लगी है। गत एक सप्ताह से आवक कमजोर हो रही थी और सात सौ 1100 कट्टे बिकने आ रहे थे, वहीं शनिवार को 1343 कट्टों की आवक हुई। व्यापारियों की माने तो इन दिनों देश के कई हिस्सों में गर्मी ज्यादा होने से लहसुन की मांग कमजोर बनी हुई है।

रकबा बीते साल से जरूर बढ़ा

किसान प्रेम सिंह गुर्जर, ज्ञान सिंह सिंह वर्मा ने बताया कि इस साल भी लहसुन के भाव काफी अच्छे हैं। शुरुआत में अच्छी क्वालिटी का लहसुन 25 से 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा था। फरवरी में दाम कम हो गए थे लेकिन अब रोज दामों में इजाफा हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के लहसुन के दाम 15 से 16 हजार रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। रकबा बीते साल से जरूर बढ़ा है, लेकिन पैदावार कम है। व्यापारियों के अनुसार स्टाक के लायक अभी माल आ रहा है। जितना अच्छा माल सीजन के बाद में किसानों के पास होगा, उतने ही अच्छे दाम उन्हें मिलेंगे।

लहसुन के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। प्याज भी अभी रोजाना आवक 4500 से 5500 क्विंटल प्रतिदिन हो रही है। निर्यात हटने से अभी आवक में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। डिमांड बढ़ेगी तो भाव में तेजी जरूर आएगी।

- शिव प्रसाद राजपूत, सचिव कृषि उपज मंडी

फर्जी किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेच सैंकड़ों क्विंटल सरसों, खरीदी में उजागर हुआ गड़बड़ झाला

असली किसानों की फसल अमानक बताकर की जा रही रिजेक्ट, नकली किसानों की बिना पंजीयन हो रही खरीद

श्योपुर। जागत गांव हमार

एक और तो शासकीय समर्थन मूल्य पर खरीद करने वाली एजेंसी किसानों की फसल को नमी व कचरा युक्त बताकर रिजेक्ट कर देती है। वहीं दूसरी ओर फर्जी किसानों की फसल को बिना ऑनलाइन पंजीयन कराए ही खरीदकर उन्हें सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ दे रही है। फर्जी किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर फसल बेचने और खरीद एजेंसी द्वारा किए गए गड़बड़ झाले को कलेक्टर लोकेश कुमार ने सूझ बूझ के साथ उजागर किया। इसके बाद अब वह एजेंसियां जिन्होंने खरीद में गड़बड़ी की है अपने पाप छुपाने के प्रयास में लग गई है।

शाखा प्रबंधक विपणन सहकारी संस्था द्वारा सरकारी समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद एजेंसी, सेवा सहकरिता संस्था आसिदा (5 किसान) सेवा सहकारिता संस्था श्योपुर (एक किसान) के प्रबंध को जारी किए गए नोटिस में उल्लेख है कि आपके द्वारा जिन किसानों की सरसों बेच जाने के नाम पर राशि चढ़ाई गई है उन किसानों का भूमी सर्वे नंबर अंकित कर दिया है, जो पहले ही अन्य समर्थन मूल्य पर पहले ही फसल बेच चुके हैं। इसकी शिकायत उन किसानों ने की थी जिनके नाम पर दोबारा सरसों बेचने का फर्जीवाड़ा किया गया। मामले में खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें जिन किसानों के नाम से फर्जीवाड़ा किया गया है उन्हें पहले से ही अन्य केंद्रों पर फसल बेचने का उल्लेख है। कुल मिलाकर यह मामला व्यापारियों की फसल को किसानों के नाम चढ़कर समर्थन मूल्य पर बेचकर बंदर बांट करने का प्रतीत हो रहा है।

जिनके पास नहीं जमीन उन्हें भी बना दिया किसान

समर्थन मूल्य में फर्जीवाड़ा किस कदर हुआ है इसके बानगी यह है कि कई किसानों को तो उनकी जानकारी के अभाव में ही उनके नाम से अन्य खरीद केंद्रों पर फसल बेचना बता दिया, जिसमें उनके नाम के साथ-साथ उनकी भूमि सर्वे क्रमांक और वह सब अभिलेख लगे हुए हैं जो पंजीयन करते समय संबंधित किसान ने लगाए थे साथ ही 6 ऐसे किसानों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं है। लेकिन उनके नाम पर 25-25 क्विंटल फसल बेचे बेचना चढ़ाया गया है। हालांकि इन किसानों के पास जिले में कहीं भी खेती किसानी के लायक जमीन नहीं है, लेकिन संबंधित खरीद एजेंसी ने उनके नाम के आगे उनकी जमीन का भूमि सर्वे क्रमांक आदि चढ़ाया हुआ है।

ऐसे करती है खरीद एजेंसी फर्जीवाड़ा

शासकीय समर्थन मूल्य पर किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा हमेशा से होता चला आया है। दरअसल, व्यापारी अपनी फसल को जिले से बाहर बेचने के बजाय समर्थन मूल्य पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं, इसके लिए उन्हें अधिकारियों से सांठ गांठ करनी होती है। अधिकारी सूची में पहले से ही चढ़े किसानों के नाम उनकी जमीन सर्वे नंबर दूसरे केंद्र पर चढ़ाकर उस फसल को बेचना बता देते हैं जो व्यापारी की होती है। ऐसी फसल को किसान के नाम पर बेचकर व्यापारी मोटा मुनाफा कामाता है जिसमें संबंधित खरीद एजेंसी का भी हिस्सा होता है।

मोबाइल पर मैसेज आया तब पता चला फर्जीवाड़ा का

किसानों के नाम पर व्यापारियों की फसल खरीद कर अपने बारे होने वाली गड़बड़ी खरीद एजेंसियां किस प्रकार करती है इसका खुलासा तो धीरे-धीरे होता जा रहा है, पर इस गड़बड़ झाले को उजागर करने का काम कुछ जागरूक किसानों ने किया दर असल कुछ किसान जिन्होंने अपनी फसल दूसरे खरीद केंद्र पर बेची थी उन्हें दोबारा से फसल बेचने के मैसेज आए इस मैसेज को लेकर जब किसान संबंधित एजेंसी के पास पहुंचे तो कई किसानों को तो एजेंसी ने समझा दिया कि सॉफ्टवेयर की गलती से दोबारा मैसेज आ गया है लेकिन कुछ जागरूक किसानों ने इसमें गड़बड़ झाला होने की आशंका जताते हुए कलेक्टर से शिकायत कर दी थी इसकी जांच में पता चला कि खरीद एजेंसी ने किसानों के नाम और उनकी जमीन के नंबर चढ़कर व्यापारियों की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचकर जो लाभ सरकार किसान को मिलना था वह लाभ व्यापारी को दिला दिया।

कृषि विज्ञान केंद्र पर जैविक उत्पाद पर प्रशिक्षण 6 जून से

उम्मीदवारों का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर होगा

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर में तीन दिवसीय जैविक उत्पाद प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन तय समय तक की स्वीकार किए जा जाएंगे। जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास एवं 2 वर्ष जैविक कृषि का अनुभव अनिवार्य की गई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम ने बताया कि जैविक उत्पाद पर व्यवसाय करने के इच्छुक कृषक, बेरोजगार युवक-युवतियां एवं छात्र/छात्राएं इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा की जाएगी। उम्मीदवार आवेदन के साथ 10 वीं अंकसूची, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर एवं पासपोर्ट साईज की फोटो की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करें। आवेदन प्राप्त उम्मीदवारों का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा। कार्यालय, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर चयनित उम्मीदवारों को 5 जून तक मोबाईल नम्बर द्वारा सूचित किया जाएगा।

बुरहानपुर में आंधी से केले की फसलों को भारी नुकसान

बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आंधी-तूफान से केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार से मांग की है कि किसानों को सर्वे करा कर मुआवजा दिया जाए। मध्य प्रदेश में मौसम में हो रहे रोज परिवर्तन के चलते जहां आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं बुरहानपुर में केले की खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल यहां तेज आंधी के चलते केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार सर्वे कराकर राहत राशि देने की मांग की है।

आरबीसी 6-4 के तहत हो राहत राशि का वितरण- अरुण यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बुरहानपुर जिले में तेज आंधी तूफान की वजह से केले की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से मांग कि अन्नदाताओं को तत्काल आरबीसी 6-4 के तहत राहत राशि वितरण करें एवं राजस्व अमले से फसलों का सर्वे कराएं, जिससे प्रभावित किसानों को उनकी फसलों की मुआवजा राशि प्राप्त हो सके।

प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है केले की खेती| मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला केले की खेती में सबसे आगे है। यहां का नाम मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में केले के कारण जाना जाता है। बुरहानपुर एक प्रमुख केला उगाने वाला जिला है। बुरहानपुर में होने वाली केले की खेती देश के साथ विदेशों में अपनी पहचान बनाई है।

केवीके अशोकनगर में फल सब्जी परीक्षण दिया गया

अशोकनगर। जागत गांव हमार

गत दिनों फल एवं सब्जी परीक्षण प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में आयोजित किया गया। जिसमें दीनदयाल राज्य आजीविका मिशन गरेठी,पिपरेसरा एवं खिरिया की दीदीयों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक अनीता जैन ने टमाटर सॉस, आम का अचार, आंवला केंडी के बारे में जानकारी प्रदान कर टोमेटो सॉस तथा सोया दूध एवं पनीर भी बनाए गए। महा प्रबंधक उद्योग एवं व्यापार केंद्र प्रकाश चंद इंदौरे ने फल एवं सब्जियों पर आधारित उत्पादन बनाने के लिए व्यवसाय स्थापित करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

फूड सेफ्टी अधिकारी लीना नायक ने खाद्य सामग्री के व्यापार हेतु आवश्यक लाइसेंस एवं फूड सेफ्टी मेजर्स के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर केंद्र प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस गुप्ता ने व्यवसाय स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग की बात कही। केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. केके यादव ने प्रशिक्षण का समन्वय किया। डॉ. वीके जैन एवं डॉ. हेमंत त्रिवेदी ने भी जानकारी प्रदान की।

कृषक संगोष्ठी में बताई लघु धान्य फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीक

वैज्ञानिक तरीके से कोदो-कुटकी की खेती बनेगी लाभ का धंधा

मंडला। जागत गांव हमार

मंडला विकासखंड के ग्राम खारी और घुघरी विकासखंड के सलवाह में कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कोदो कुटकी, रागी, कंगनी और सांवा लघु धान्य फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीक, जैविक खेती के बढ़ते महत्व तथा खरीफपूर्व आवश्यक तैयारी के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

खारी में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उपसंचालक कृषि मधु अली द्वारा बताया गया कि मिलेट्स कम उपजाऊ भूमि के लिए वरदान है। कम लागत में किसान मिलेट्स का उत्पादन लेकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। औषधीय गुण होने के कारण अब कोदो कुटकी एवं अन्य लघु धान्य फसलों की मांग बढ़ती जा रही है और मांग अनुरूप किसानों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि कोदो-कुटकी की खेती में उन्नत तकनीक, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग तथा खेती में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करें।

मिलेट्स कम उपजाऊ भूमि के लिए वरदान

प्रशिक्षण में उप संचालक कृषि मधु अली, सहायक संचालक नेहा डेहरवाल, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जेआर गजेंद्र, कृषि विस्तार अधिकारी रामकिशोर सैयाम, निधि, पुष्पा कोरचे उपस्थित थे।

कृषि में करें उन्नत तकनीक का उपयोग: प्रशिक्षण में कृषकों को खेती में जैविक खाद का उपयोग, उन्नत प्रमाणित बीज की जानकारी और कतार बोनी की जानकारी दी गई। कोदो-कुटकी, रागी आदि मोटे अनाज की खेती में जैविक खाद का महत्व एवं उपयोग विधि के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण में कृषकों को अन्य खरीफ फसलों की फसल उत्पादन तकनीक और बारिश पूर्व तैयारियों, फसल बीमा, उन्नत यंत्रों की जानकारी एवं ऑनलाइन पंजीयन पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण: उपसंचालक मधु अली द्वारा महिष्मति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा संचालित कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई बम्होरी और बकोरी में स्थापित शिवम कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया गया।

मिट्टी परीक्षण का मुख्य उद्देश्य मिटटी में सही मात्रा में पोषक तत्व डालना

मृदा परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों बताए मिटटी के पोषक तत्व

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा संचालित निकरा परियोजना जलवायु समुत्थानुशील कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार के अंतगज़्त अंगीकृत ग्राम कोडिया ब्लॉक जतारा जिला टीकमगढ़, में मिट्टी परिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि में भौतिक एवं रासायनिक संरचना तथा उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति को ज्ञात करने के लिये मृदा का विश्लेषण करना ही मृदा परीक्षण कहलाता है। प्रत्येक पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी से पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषक सही मात्रा में फसल के अनुसार पोषक तत्व डाले। खाद एवं उर्वरक के माध्यम से मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार सही प्रकार की रासायनिक और जैविक खाद का उपयोग होना चाहिए। मिट्टी के रासायनिक परिक्षण से मिट्टी उपयुक्तता के आधार पर फसल की अधिक पैदावार के लिए बिल्कुल सही अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्य मिट्टी की जांच मुख्य बिन्दुओं के लिए की जाती है जैसे-जीवांश या कार्बनिक पदार्थ, मिट्टी में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा, पीएच मूल्य या अम्लता, क्षारीयता, घुलनशील लवण या विद्युत चालकता, उपज बढ़ाने के लिए उर्वरक की कितनी मात्रा देना आवश्यक है। खेत से मिट्टी का नमूना लेने की विधि कुछ इस प्रकार है - मिट्टी का नमूना एकत्र करने के लिए खेत में कम से कम 16-20 जगहों का चुनाव किया जाए। इन स्थानों की ऊपरी सतह का कूड़ा-कचरा, खरपतवार आदि खुरचकर साफ कर लेना चाहिए, फावड़ा या खुरपी से नमूना एकत्रित करना है तो मृदा में व्ही (ट) के आकार का लगभग 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते है। इस गड्ढे की दीवार से मृदा की ऊपरी सतह से डेढ़ से दो सेमी. मोटी परत काटते हैं और इस प्रकार कटी हुई मृदा को एकत्रित कर लेते हैं। इन सभी नमूनों को एक साफ कपड़े या तसले या ट्रे में रखकर भली प्रकार मिला लेते हैं, इन सभी नमूनों को हाथ या खुरपी की सहायता से अच्छी तरह मिला लेते हैं।

खेत की मिट्टी नहीं होगी खराब और बना रहेगा पर्यावरण का संतुलन

मिट्टी मिलाते समय कंकड़-पत्थर आदि के टुकड़े, पौधों की जड़े और अवशेष आदि निकाल कर अलग कर देते हैं, फिर नमूने का एक ढेर बना लेते हैं। इन नमूनों को चार भागों में बांट लेते हैं। इनमें से आमने-सामने के दो भाग हटा देते हैं। शेष दो भागों की मिट्टी का पुन: ढेर बनाकर फिर से चार भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहले की भांति आमने सामने के दो भागों को पुन: मिलाकर ढेर बना लेते हैं। यह क्रिया तब तक इसी प्रकार दोहराते रहें, जब तक लगभग मिट्टी की मात्र आधा किलोग्राम मिट्टी शेष रह जाए। इस नमूने को कपड़े की थैली में भरकर एक नमूना पत्रक (जिसमें कृषक का नाम, पता, खेत का नाम या नम्बर, जीपीएस, बोई जाने वाली फसल, नमूने लेने का दिनांक, खेत का क्षेत्रफल आदि लिखा हो) थैली के अंदर डालते हैं। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. बीएस किरार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. यूएस धाकड़ और जयपाल छिगारहा सहित 35 कृषक उपस्थित रहे। मिट्टी परीक्षण अभियान केंद्र द्वारा पूरे जून माह भर किसानो में जागरूकता लेन के लिए चलाया जा रहा है। जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य को सही रखने में कृषकों में जागरूकता और अधिक मात्र में खाद, उर्वरक अनावश्यक रूप से उपयोग करने से एक तो खेती की लागत बढ़ाती है और दूसरी खेत की मिट्टी भी खराब होती है जिससे पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है।

पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

शिविर में 25 गाय, 47 भैंस 71 बकरियों का किया इलाज

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा संचालित निकरा परियोजना जलवायु समुत्थानुशील कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार के अंतर्गत अंगीकृत ग्राम को डिया ब्लॉक जतारा जिला टीकमगढ़, में पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

पशु स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का मुख्या उद्देश्य किसानों के बीच उनके पशुओं के रोग, कीट, पोषण एवं रखरखाव के प्रति जागरुकता लाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गाय भैंस एवं बकरी आदि की बीमारियां जैसे खुरपका मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार ब्रूसेलोसिस, रेबीज, एंथ्रेक्स थाइलेरियोसिस, थनैला एवं कीट जैसे चिचड़, मक्खी, पेट के कीड़े इत्यादि का इलाज, टीकाकरण एवं बचाव के लिए जानकारी दी गई। संतुलित आहार की विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित एवं संचालित पशु पोषण एप्लीकेशन मोबाईल में डाउनलोड करने के बारे में शिखाया गया। पशु स्वास्थ्य शिविर में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. बीएस किरार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. यूएस धाकड़ एवं जयपाल छिगारहा एवं पशुपालन विभाग से एवीएफओ डॉ. मनीष प्रजापति सहित 45 कृषक उपस्थित रहे। शिविर में 25 गाय, 47 भैंस व 71 बकरियों का इलाज किया गया।

पांढुर्ना में अधिकारियों ने किया कृषि आदान केंद्रों का निरीक्षण

पांढुर्ना। जागत गांव हमार

क्षेत्र के किसान खरीफ सत्र की तैयारियों में जुट गए हैं। फसल के लिए आवश्यक खाद बीज खरीदने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री मिले, इसके लिए कलेक्टर के निदेज़्श पर राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों ने पांढुर्ना के कृषि आदान केंद्रों का निरीक्षण कर बीज तथा कीटनाशकों के नमूने एकत्रित किए। इस निरीक्षण दल में अनुविभागीय अधिकारी नेहा सोनी, तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, एसडीओ कृषि दीपक चौरसिया, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सुनील गजभिए, कृषि विस्तार अधिकारी किशोर डिगरसे और विनोद लोखंडे शामिल थे।

महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायत ने सीएसआर का लालच ठुकराया, एकमत से लिया निर्णय

मेहरागांव पंचायत का फैसला, अब हम अपनी नदियां बचाएंगे, नहीं होने देंगे रेत का उत्खनन

महिलाओं की एक जुटाता से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर भी चौंके

नरसिंहपुर। डॉ. ब्रजेश शर्मा

जिले के सांईखेड़ा ब्लॉक के गांव ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। इस गांव में प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लोक सुनवाई हुई और यहां की सरपंच ने अपने उपसरपंच और पंचों के साथ मिलकर ये ऐलान कर दिया कि वे अपनी नदियों और प्राकृतिक संपदा को बचाएंगे। इस लोक सुनवाई में एक साथ निर्णय पारित करते हुए इस पंचायत ने कहा कि नदियों और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन पाप है वह अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से रेत निकालने नहीं देंगे। इस निर्णय को सुनकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी चौंक गए। विकासखंड साईंखेड़ा के ग्राम मेहरागांव में मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रेत खदान मेहरागांव में 22 मई को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का आयोजन मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा किया गया था।

रेत के अंधाधुंध दोहन व परिवहन से ग्रामीण त्रस्त

मेहरागांव रेत खदान खसरा क्रमांक 380 में स्थित है, जहां करीब 20 हेक्टेयर अर्थात 50 एकड़ रकबे से 3 लाख 24000 घन मीटर सालाना रेत का उत्खनन प्रस्तावित है। पिछले कई वर्षों से यहां रेत का अंधाधुंध खनन हो रहा है। यह जिले की सबसे बड़ी उम्दा किस्म की बड़ी रेत खदान है। रेत के अंधाधुंध दोहन व परिवहन से ग्रामीण त्रस्त रहे हैं। गांव की सड़कें भारी वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन अब जब 22 मई 2024 बुधवार को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने लोक सुनवाई का आयोजन किया और खनिज महकमें के एक युवा मैनेजर ने लोक सुनवाई के दौरान खनन के फायदे बताते हुए ग्रामीणों से कहा कि आप खनन का प्रस्ताव देंगे तो हम यहां सीएसआर के तहत 2 लाख रुपए सालाना पंचायत को अतिरिक्त आय के रूप में देंगे। स्वास्थ्य के लिए एक इमरजेंसी यूनिट रखेंगे। इतना कहते ही ग्रामीण यह कहने लगे कि आप हमसे ही दो के बदले चार लाख लीजिए, लेकिन हम रेत खनन नहीं करने देंगे।

लोक सुनवाई में सभी महिला पंच, उपसरपंच और सरपंच मौजूद रहीं

इस लोकसुनवाई में मेहरागांव की सभी महिला पंच, उपसरपंच और सरपंच मौजूद रहीं। बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों की उपस्थिति में बोर्ड व जिला प्रशासन के अधिकारी उस समय सकते में आ गए जब पंचायत ने एक साथ मिलकर यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि नदियों और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन पाप है और वह अब किसी भी हालत में अपने पंचायत क्षेत्र से रेत का उत्खनन नहीं होने देंगे।

पंचायत ने डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन

समूची ग्राम पंचायत के इस निर्णय से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिला प्रशासन के अधिकारी सकते में आ गए। पंचायत ने रेत खनन नहीं कराए जाने को लेकर एक ज्ञापन यहां जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए डिप्टी कलेक्टर को भी सौंपा। पंचायत के इस निर्णय से मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी सकते में है कि अब यह तकनीकी समस्या हो गई है कि पंचायत ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से रेत खनन नहीं होने देंगे।

नदियों और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन राकने लिया निर्णय

इसके बाद पूरे गांव ने एक साथ एक आवाज में निर्णय लेते हुए यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि वह अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से किसी भी हालत में रेत का खनन नहीं होने देंगे। नदियों और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन पाप है इसलिए वह अपने पंचायत क्षेत्र से रेत नहीं निकलने देंगे।

आसरे ने ग्रामीण-शहरी विभाजन को एकजुट करने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का विस्तार किया

डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच एक बुनियादी अधिकार

भोपाल। एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल रूरल एम्पावरमेंट (आसरे)को अपने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण निवासियों को महत्वपूर्ण डिजिटल कौशल और ऑनलाइन संसाधन प्रदान करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करना है। यह पहल

डिजिटल युग में समावेशिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आसरे के समर्पण को प्रदर्शित करती है। आज की डिजिटल दुनिया में,सामाजिक और आर्थिक समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी और साक्षरता तक पहुंच महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी है,जिसके परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन हुआ है। इस असंतुलन को पहचानते हुए आसरे ने इस मुद्दे के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और ग्रामीण निवासियों को आवश्यक डिजिटल कौशल और ज्ञान से लैस किया है। आसरे के अध्यक्ष डॉ.पंकज शुक्ला ने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के विकास पर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच एक बुनियादी अधिकार है जो हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे उनका स्थान या सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का विस्तार करके, आसरे का लक्ष्य ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाना है। आसरे भी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को सशक्त बना रहा है।

बुनियादी डिजिटल कौशल सिखाएगा आसरे

आसरे के नेतृत्व में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रारंभ में यह ग्रामीण निवासियों को व्यापक प्रशिक्षण सत्र प्रदान करेगा, उन्हें कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करने के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ,एप्लिकेशन नेविगेट करने और सायबर फ्रॉड से बचने के उपाय जैसे बुनियादी डिजिटल कौशल सिखाएगा। ये सत्र स्थानीय भाषाओं में आयोजित किए जाएंगे और ग्रामीण समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किए जाएंगे। दूसरे, आसरे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ग्रामीण निवासियों के पास शैक्षिक सामग्री,सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल जानकारी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच हो। इन संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके, आसरे का उद्देश्य ग्रामीण व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने और उनके समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना है। अंत में, कार्यक्रम में डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे जिनका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ग्रामीण निवासियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये कार्यशालाएं ज्ञान साझा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और सहायक वातावरण में डिजिटल कौशल विकसित करने के लिए मंच के रूप में काम करेंगी। आसरे के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. रंजन कुमार ने आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशिता को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज की अर्थव्यवस्था में भागीदारी और सफलता दोनों के लिए डिजिटल साक्षरता का होना आवश्यक है। आसरे कार्यक्रम ग्रामीण व्यक्तियों को नए अवसरों का लाभ उठाने और अधिक समावेशी और निष्पक्ष समाज को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आसरे अपने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम की समृद्धि और दीर्घायु की गारंटी देने के लिए समर्पित है, जो वंचित ग्रामीण समुदायों और हाशिए पर रहने वाले समूहों तक पहुंचने पर केंद्रित है। डिजिटल पहुंच में अंतर को कम करके, आसरे ग्रामीण भारत की पूरी क्षमता को उजागर करना चाहता है और अधिक समृद्ध और परस्पर जुड़े भविष्य की ओर ले जाना चाहता है।

मालवा-निमाड़ के 90 प्रतिशत अमृत सरोवरों में पानी ही नहीं

इंदौर। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक जिले में वर्षाकाल में बरसने वाले अनमोल जल का संग्रहण करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से अमृत सरोवर तैयार किए गए थे। उम्मीद थी कि ये सरोवर वर्षा का जल सहेजेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है। मालवा-निमाड़ के जिलों में बनाए अमृत सरोवरों की पड़ताल की तो 90 फीसद सरोवरों में पानी ही नहीं है। इन सरोवरों के निर्माण में तकनीकी मापदंड और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया। देश में जल संरक्षण के लिए पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत करोड़ों रुपए में बने इन सरोवरों को लगता है कि बनाए जाने के बाद पलटकर नहीं देखा गया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)